मुख्यमंत्री ने इन्टीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एण्ड लॉजिस्टिक क्लस्टर की लॉचिंग की

नया उ0प्र0 विकसित भारत की संकल्पना में अपनी भूमिका के निर्वहन के लिए स्वयं को तैयार कर रहा

❑ डबल इंजन सरकार ने विगत 08 वर्षों में उ0प्र0 को एक्सप्रेस-वे स्टेट के रूप में स्थापित करने में बड़ी भूमिका का निर्वहन किया : मुख्यमंत्री

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डबल इंजन सरकार ने विगत 08 वर्षों में उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेस-वे स्टेट के रूप में स्थापित करने में बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। हमें उत्तर प्रदेश को इन्वेस्टमेन्ट के एक बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने में भी सफलता प्राप्त हुई है। एक्सप्रेसवेज को प्रदेश की इकोनॉमिक ग्रोथ का बैक बोन बनाने की दृष्टि से आज उत्तर प्रदेश में इन्टीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एण्ड लॉजिस्टिक क्लस्टर की लॉचिंग की गई है। यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए देखे गये सपने के साकार होने जैसा है।

मुख्यमंत्री अपने सरकारी आवास पर 27 इन्टीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एण्ड लॉजिस्टिक क्लस्टर की लॉचिंग करने के उपरान्त अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने प्रदेश में संचालित और निर्माणाधीन एक्सप्रेसवेज की प्रगति की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि यह पहली बार हुआ है कि एक्सप्रेस-वे के रूप में इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के साथ ही, प्रदेश में इण्डस्ट्रियल क्लस्टर और कॉरिडोर का विकास भी किया जा रहा है। डिफेन्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के 06 नोड प्रदेश में पहले से ही बन रहे हैं, लेकिन यह 06 नोड एक्सप्रेस-वे पर नहीं बन रहे हैं। इनको भारत सरकार की सहमति से हमने स्थापित किए थे। वहां पर इससे जुड़ा इन्वेस्टमेन्ट हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन्टीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एण्ड लॉजिस्टिक क्लस्टर का विकास प्रदेश के लिए एक युग परिवर्तक घटना के रूप में माना जा सकता है। 05 एक्सप्रेस-वे के दोनों ओर 13,240 एकड़ से अधिक भूमि में एक साथ 27 ऐसे क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। यह नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर है, जिसने अपने आपको बीमारू राज्य से भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में प्रस्तुत किया है। नया उत्तर प्रदेश विकसित भारत की संकल्पना में अपनी भूमिका के निर्वहन के लिए स्वयं को तैयार कर रहा है। यह एक बड़ा अभियान है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षा, लैण्डबैंक, बेहतरीन इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा कनेक्टिविटी इन्वेस्टमेन्ट की अनिवार्य शर्तें हैं। यह सभी आज उत्तर प्रदेश में निवेशकों के लिए उपलब्ध है। सभी एक्सप्रेस-वे पर सर्विस लेन की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उन्होंने स्वयं गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे पर 91 किलोमीटर की यात्रा सड़क मार्ग से तय की है। यह तेज रतार के साथ-साथ आरामदायक भी था। यह आज के उत्तर प्रदेश के इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थिति है, जिस मामले में पहले राज्य पिछड़ा माना जाता था। जिस प्रदेश में कोई इन्वेस्टमेन्ट के लिए नहीं आना चाहता था, आज वहां इन्वेस्टमेन्ट हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें औद्योगिक निवेश के लिए भूमि की कीमत को कम करने तथा हॉरिजेन्टल के स्थान पर वर्टिकल उद्योगों की स्थापना की दिशा में प्रयास करने चाहिए। औद्योगिक विकास से जुड़े हुए हमारे जितने भी प्राधिकरण हैं, उनमें मैनपावर की पर्याप्त उपलब्धता होनी चाहिए। यह अच्छे परफॉर्मेंस की पहली शर्त है। उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जिस दिशा में आगे बढा है, इन कार्यों से हम नई सोच के साथ देश के सामने एक मॉडल प्रस्तुत कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन्टीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एण्ड लॉजिस्टिक क्लस्टर की स्थापना एक अच्छी शुरूआत है। यह 27 क्लस्टर आने वाले समय में एक्सप्रेस-वे की तस्वीर को बदलने तथा उत्तर प्रदेश को औद्योगिक निवेश के बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करेंगे। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश में आने वाले निवेशकों की भावनाओं के अनुरूप हम इन्टीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एण्ड लॉजिस्टिक क्लस्टर को एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने में सफल होंगे।

इस अवसर पर औद्योगिक विकास मंत्री नन्द कुमार गुप्ता 'नन्दी' ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को देश के सर्वोत्तम राज्य के रूप में पहचान दी है। उन्होंने विगत 08 वर्षों में प्रदेश की तस्वीर और तकदीर को बदलने का कार्य किया है। आज हमारा प्रदेश एक्सप्रेस-वे स्टेट के रूप में पहचान बना रहा है।

मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा कि प्रदेश के इतिहास में यह पहली बार हुआ है, जब शासन ने 15 हजार करोड़ रूपये से अधिक की धनराशि औद्योगिक प्राधिकरणों को भूमि क्रय करने तथा औद्योगिक क्षेत्र का विकास करने के लिए उपलब्ध करायी है। यह मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है। यह प्रदेश में औद्योगीकरण को बड़ा बूम देगा।

इस अवसर पर औद्योगिक विकास राज्य मंत्री जसवन्त सिंह सैनी, मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह, प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आलोक कुमार, एम0एस0एम0ई0 सचिव प्रांजल यादव एवं यूपीडा के अधिकारी उपस्थित थे।

ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कारीडोर के अन्तर्गत प्रदेश के 06 जनपदों चित्रकूट, झांसी, कानपुर, अलीगढ़, लखनऊ व आगरा में कुल 5,184 एकड़ क्षेत्र में डिफेंस नोड्स को स्थापित किया जा रहा है। इसमें से 5,017 एकड़ क्षेत्रफल प्राधिकरण द्वारा अर्जित किया जा चुका है।

माह जून में आबकारी विभाग ने 4458.22 करोड़ रूपये राजस्व अर्जित किया

लखनऊ। प्रदेश के आबकारी एवं मद्यनिषेध राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नितिन अग्रवाल ने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के माह जून, 2025 में आबकारी विभाग ने 4458.22 करोड़ रूपये राजस्व अर्जित किया है, जो गत वर्ष इसी माह में अर्जित किये 3431.20 करोड़ रूपये राजस्व के सापेक्ष 1027.02 करोड़ रूपये अर्थात लगभग 30 प्रतिशत से अधिक है। उन्होंने बताया कि माह अप्रैल-जून तक तिमाही माह में 14400 करोड़ रूपये निर्धारित राजस्व लक्ष्य के सापेक्ष 14229 करोड़ रूपये लगभग 98.8 प्रतिशत राजस्व प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है, जो गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में इसी अवधि अर्जित राजस्व 11783.76 करोड़ रूपये की तुलना में 2445 करोड़ रूपये लगभग 20 प्रतिशत से अधिक है।

आबकारी मंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में माह जून, 2025 तक प्रदेश में अवैध शराब के निर्माण, बिकी एवं तस्करी के कुल 29,784 अभियोग दर्ज करते हुए 7.72 लाख लीटर अवैध मदिरा बरामद की गयी। अवैध मदिरा के कारोबार में संलिप्त 5,559 व्यक्तियों को गिरतार करते हुए 1,075 व्यक्तियों को जेल भेजा गया तथा अवैध मदिरा की तस्करी में संलिप्त 35 वाहनों को जब्त किया गया। उन्होंने बताया कि गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में माह जून, 2025 तक प्रदेश में अवैध शराब के निर्माण, बिकी एवं तस्करी के कुल 27,276 अभियोग दर्ज करते हुए 7.38 लाख लीटर अवैध मदिरा बरामद की गयी थी। अवैध मदिरा के कारोबार में संलिप्त 6,426 व्यक्तियों को गिरतार करते हुए 2,062 व्यक्तियों को जेल भेजा गया था तथा अवैध मदिरा की तस्करी में संलिप्त 50 वाहनों को जब्त किया गया था।ने बताया कि वर्ष 2025-26 में दिनांक 06.06.2025 से 20.06.2025 तक 15 दिवस का विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया गया। इस अभियान के अन्तर्गत 5,079 अभियोग दर्ज करते हुए 1,42,401 ली. अवैध शराब बरामद की गयी। अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त 924 व्यक्तियों को गिरतार किया गया तथा 189 अभियुक्तों को जेल भेजा गया। मदिरा के परिवहन में संलिप्त कुल 03 वाहन जब्त किये गये।

गाजियाबाद के मोदीनगर में डॉ. के.एन. मोदी विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोकभवन, लखनऊ में सम्पन्न हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में उच्च शिक्षा विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। प्रदेश में निजी क्षेत्र के एक नए विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में संरचनात्मक सुधारों और संस्थागत विस्तार पर विशेष बल दिया है। इसी क्रम में गाजियाबाद जनपद के मोदीनगर में डा. के.एन. मोदी विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी गई है। यह विश्वविद्यालय डा. के.एन. मोदी इंस्टीट्यूट आफ फार्मास्यूटिकल्स एजुकेशन एण्ड रिसर्च ट्रस्ट द्वारा ग्राम बिसोखर व बेगमाबाद बुदाना, तहसील-मोदीनगर में लगभग 20.45 एकड़ भूमि पर स्थापित किया जाएगा।

प्रस्ताव के अनुसार उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 में संशोधन कर 'उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2025' प्रख्यापित किया जाएगा, जिसके पश्चात विश्वविद्यालय को संचालन प्राधिकृति पत्र जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु यह एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगारपरक शिक्षा का अवसर प्राप्त होगा।

सहकारिता

संरक्षक
योगेश कुमार (आई.ए.एस.)
आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता, उ0प्र0

श्रीकान्त गोस्वामी
प्रबन्ध निदेशक/प्रधान सम्पादक

सवीन्द्र सिंह
महाप्रबन्धक

स्वत्वाधिकारी, यू0पी0 कोऑपरेटिव यूनियन लि0, प्रकाशक, मुद्रक सुनील कुमार दिवाकर द्वारा सहकारी प्रेस, 14, डॉ0 भीमराव अम्बेडकर मार्ग लखनऊ, उ0प्र0 से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक-सुनील कुमार दिवाकर
फोन : 0522-4004577 (का.)
मोबाइल : 9415094114
ईमेल : sahkarita@gmail.com

सभी विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ ही मान्य होगा।

सूचना

इस अंक के साथ निम्नलिखित बैंक की बैलेन्सशीट प्रकाशित की जा रही है-

1. जिला सहकारी बैंक लि0, जौनपुर।

प्रदेश सरकार के मुख्य कर-करेत्तर राजस्व वाले मदों में जून, 2024 के सापेक्ष जून, 2025 में रु0 1058.23 करोड़ की वृद्धि

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि प्रदेश सरकार के मुख्य कर-करेत्तर राजस्व वाले मदों में वित्तीय वर्ष 2025-26 के जून माह में कुल रु0 17982.96 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ जबकि वित्तीय वर्ष 2024-25 के जून माह में रु0 16924.73 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ था। इस प्रकार गत वर्ष माह जून की तुलना में वर्तमान वित्तीय वर्ष के माह जून में मुख्य कर-करेत्तर राजस्व प्राप्ति के प्रमुख मद के अंतर्गत रु0 1058.23 करोड़ राजस्व अधिक प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही मे कर राजस्व के अंतर्गत रु0 72620.18 करोड़ लक्ष्य के सापेक्ष रु0 54186.64 करोड़ की प्राप्ति हुई है जो माह जून तक राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य का 74.6 प्रतिशत है।

वित्त मंत्री ने बताया कि माह जून 2025 में राज्य कर के अंतर्गत राजस्व प्राप्ति के निर्धारित लक्ष्य रु0 14610.26 करोड़ के सापेक्ष रु0 9696.53 करोड़ की प्राप्ति हुई है जो निर्धारित लक्ष्य का 66.4 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि जून 2024 में राज्य कर के अंतर्गत प्राप्ति रु0 9483.18 करोड़ थी। जी.एस.टी. के अन्तर्गत माह जून, 2025 में कुल रु0 6645.52 करोड़ की राजस्व प्राप्ति हुई जबकि गत वर्ष जून, 2024 के माह में प्राप्ति रु0 6656.54 करोड़ रही थी।

आर0 एन0 आई0 नं0 : 25008/72

डाक पंजी0 सं0 - GPO- LW/NP-178/2024-26

सहकारिता

उत्तर प्रदेश के सहकारी आन्दोलन का दर्पण

वर्ष : 53 अंक : 41 (हिन्दी साप्ताहिक) लखनऊ-वृहस्पतिवार 10 जुलाई, 2025 से 16 जुलाई, 2025 पृष्ठ-4 वार्षिक 150.00 रूपया मात्र एक प्रति 3.00 रूपया

सहकारिता अब प्रदेश के नागरिकों के विश्वास का केंद्र बन चुकी है : जे.पी.एस. राठौर

❑ 266 महिलाओं को ड्रोन पायलट प्रशिक्षण के बाद "ड्रोन दीदी" प्रमाण-पत्र दिए गए और पांच उत्कृष्ट ड्रोन दीदियों को सम्मानित किया गया।

❑ सहकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए 05 एम-पैक्स समितियों को सम्मानित किया गया और 02 अधिकारियों को सहकारी निधि की रक्षा के लिए वीरता सम्मान मिला।

- मंत्री जे.पी.एस. राठौर

- 38 जिलों में 51 एम-पैक्स समितियों पर जन औषधि केंद्र खोले, जहाँ सस्ती जेनेरिक दवाएं मिलेंगी।
- सहकारिता सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बन चुकी है और सदस्यता महाभियान में 30 लाख नए सदस्य जुड़े।
- कृषकों को उर्वरक आपूर्ति के लिए एम-पैक्स समितियों को ब्याजमुक्त कैश क्रेडिट लिमिट दी गई है।
- सहकारी समितियों के भवनों के सुदृढ़ीकरण का कार्य चल रहा है। - मंत्री जे.पी.एस. राठौर

❑ पर्यावरण संरक्षण के लिए "एक पेड़ माँ के नाम" अभियान में सहभागिता करें।

- मंत्री डा. अरूण कुमार सक्सेना

❑ मंत्री जे.पी.एस. राठौर की अध्यक्षता में सहकारिता मंत्रालय का चतुर्थ स्थापना दिवस कार्यक्रम हुआ आयोजित

लखनऊ। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, गोमतीनगर, लखनऊ में केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के चतुर्थ स्थापना दिवस के अवसर पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश सरकार के सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जे.पी.एस. राठौर ने की, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में वन, पर्यावरण, जन्तु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डा. अरूण कुमार सक्सेना ने प्रतिभाग किया।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के "सहकार से समृद्धि" के विजन को मूर्तरूप देने हेतु वर्ष 2021 में गठित केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय द्वारा ग्रामीण भारत को आर्थिक रूप से सशक्त करने की दिशा में कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में प्रदेश के 38 जनपदों की 51 एम-पैक्स समितियों पर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों का लोकार्पण मंत्री श्री राठौर द्वारा किया गया। इन केन्द्रों पर जनसामान्य को 80 से 90 प्रतिशत तक सस्ती जेनेरिक दवाएं एवं सर्जिकल उत्पाद उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे न केवल समितियों की आय बढ़ेगी, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ होंगी।

इस अवसर पर ड्रोन पायलट प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी 266 महिलाओं को "ड्रोन दीदी" प्रमाण-पत्र वितरित किए गए। इन महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से चयनित कर आईसीसीएमआरटी, लखनऊ द्वारा नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षित किया गया था। प्रशिक्षण पूरी तरह निःशुल्क रहा, जिसमें सैद्धांतिक ज्ञान, सिम्युलेटर, फील्ड परीक्षण, मरम्मत व रखरखाव से संबंधित प्रशिक्षण शामिल था। पांच उत्कृष्ट "ड्रोन दीदियों" दिव्या निषाद (गोरखपुर), मोनिका सिंह (शाहजहाँपुर), *(शेष पृष्ठ 2 पर...)*

लखनऊ में बनेगा प्रदेश का पहला बीज पार्क

लखनऊ। प्रदेश के कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने विधान भवन के समिति कक्ष संख्या-08 में बीज प्रसंस्करण उद्यमियों के साथ बैठक की। इस अवसर पर प्रस्तावित चौधरी चरण सिंह बीज पार्क की रूपरेखा प्रस्तुत की गई और नियमों, शर्तों एवं सुविधाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में 35 बीज कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए और उन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं भी साझा कीं।

श्री शाही ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत दृष्टिकोण को साकार करने के लिए उत्तर प्रदेश में पहला बीज पार्क स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह पार्क प्रदेश को बीज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाएगा। उद्यमियों के सुझावों को सम्मिलित करते हुए योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि चौधरी चरण सिंह बीज पार्क लखनऊ जनपद के मलिहाबाद क्षेत्र स्थित अटारी, नवबस्ता एवं सुरती खेड़ा गांवों में कुल 130.63 एकड़ भूमि पर स्थापित किया जा रहा है। यह भूमि राज्य .षि फार्म के अंतर्गत आती है। इस पार्क में कुल 26 औद्योगिक भूखंड विकसित किए जाएंगे, जो विभिन्न आकारों में होंगे और उन्हें 30 वर्ष की लीज पर, 90 वर्ष तक बढ़ाई जा सकने की सुविधा के साथ, बीज उत्पादन से जुड़ी संस्थाओं को आवंटित किया जाएगा।

संपादकीय

सामूहिक विकास की सशक्त नींव

भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और उनकी जीविका का मुख्य साधन कृषि, पशुपालन, कुटीर उद्योग आदि हैं। इन क्षेत्रों में आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सहकारिता (Cooperative) आंदोलन एक अत्यंत प्रभावशाली माध्यम बनकर उभरा है। "एकता में बल है" की भावना को मूर्त रूप देने वाली सहकारिता प्रणाली केवल आर्थिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक और नैतिक विकास की भी आधारशिला है।

सहकारिता का मूल उद्देश्य यह है कि एक समान उद्देश्य रखने वाले लोग मिलकर संसाधनों का साझा उपयोग करें और मिल-जुलकर लाभ कमाएं। इसमें न तो पूंजीपति की प्रधानता होती है और न ही केवल मुनाफा कमाना ही लक्ष्य होता है। सहकारी संस्थाएँ 'एक व्यक्ति, एक वोट' के सिद्धांत पर कार्य करती हैं, जहाँ प्रत्येक सदस्य का निर्णय बराबरी का होता है।

भारत में सहकारिता आंदोलन की शुरूआत 1904 में "सहकारी ऋण समितियाँ अधिनियम" के साथ हुई। स्वतंत्रता के बाद सरकार ने इसे ग्रामीण विकास, कृषि सुधार और वित्तीय समावेशन का प्रमुख हथियार बनाया। अमूल, इफको, नैफेड जैसी संस्थाएँ इसकी सफलता का प्रमाण हैं।

सहकारिता की प्रमुख उपलब्धियाँ

कृषि और कृषक कल्याण : किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक, सिंचाई साधन, तकनीकी जानकारी और ऋण की सुविधाएँ सहजता से उपलब्ध कराना।

दुग्ध उत्पादन : डेयरी सहकारी संस्थाएँ जैसे अमूल ने दुग्ध क्रांति को जन्म देकर भारत को विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बना दिया।

ग्रामीण वित्तीय समावेशन : जिला सहकारी बैंक, प्राथमिक कृषि ऋण समिति (PACS) जैसे संस्थानों ने ग्रामीण क्षेत्र में बैंकों की पहुंच सुनिश्चित की।

महिला सशक्तिकरण : महिलाओं की स्वयं सहायता समूह (SHGs) और महिला सहकारी संस्थाएँ उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभा रही हैं।

हालांकि सहकारिता आंदोलन ने अनेक उपलब्धियाँ हासिल की हैं, लेकिन इसके समक्ष कई चुनौतियाँ भी हैं जैसे : भ्रष्टाचार और राजनीतिक हस्तक्षेप, तकनीकी ज्ञान की कमी, वित्तीय कुप्रबंधन आदि।

इन समस्याओं का समाधान पारदर्शिता, डिजिटल तकनीक का समावेश, नियमित प्रशिक्षण और केंद्र-राज्य सहयोग से किया जा रहा है। वर्तमान में केन्द्र की सरकार का इस पर पूरा फोकस है। केन्द्र सरकार ने इन समस्याओं को दूर करने की दृष्टि से अलग से "सहकारिता मंत्रालय" का गठन किया है जिसका अभी प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री की अगुवाई में भव्य स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया है।

सहकारिता न केवल आर्थिक विकास की रीढ़ है, बल्कि यह सामाजिक समरसता, विश्वास और भागीदारी की संस्कृति को भी बढ़ावा देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित "सहकार से समृद्धि" का लक्ष्य तभी साकार हो सकता है जब हर नागरिक सहकारी भावना को आत्मसात करे और सामूहिक हित को व्यक्तिगत लाभ से ऊपर रखे।

"जहाँ सहयोग, वहाँ विकास" :
सहकारिता ही सशक्त भारत का आधार है।

❑

विभिन्न जनपदों के कुल 26 मार्गों के चालू कार्यों हेतु 30 करोड़ 49 लाख 50 हजार की अवशेष धनराशि की गयी अवमुक्त

लखनऊ। उ0प्र0 सरकार द्वारा राज्य सड़क निधि योजना के अन्तर्गत विभिन्न मण्डलों के विभिन्न जनपदों के कुल 26 मार्गों के स्वीकृत एवं चालू कार्यों हेतु 30 करोड़ 49 लाख 50 हजार रूपए की अवशेष धनराशि अवमुक्त की गयी है। इन 26 चालू कार्यों में जनपद अयोध्या के 04, कानपुर नगर, सहारनपुर, उन्नाव, रायबरेली, बुलन्दशहर व मिर्जापुर के 02-02 तथा महराजगंज, गोरखपुर, जौनपुर, वाराणसी, कानपुर देहात, अमेठी, झांसी, खीरी, सीतापुर व हरदोई के 01-01 कार्य सम्मिलित हैं। इस सम्बन्ध में आवश्यक शासनादेश लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है।

जारी शासनादेश में सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च 2026 तक कर लिया जाय एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को 30 अप्रैल 2026 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। शासनादेश में यह भी निर्देश दिये गये हैं कि कार्यों की वित्तीय/भौतिक प्रगति का सक्षम स्तर पर सम्यक निरीक्षण/सत्यापन कर प्रगति रिपोर्ट हर माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

पृष्ठ 1 का शेष..... सहकारिता अब प्रदेश के नागरिकों के....

अर्चना सक्सेना (अमरोहा), पूर्णिमा शर्मा (जौनपुर) और वंदना सिंह (मिर्जापुर) को मंच पर बुलाकर विशेष रूप से सम्मानित किया गया।

समारोह में सहकारिता क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रदेश की पांच एम-पैक्स समितियों शाहजहांपुर, कानपुर, इटावा, हापुड़ और रायबरेली को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। इन समितियों ने कृषि ऋण, उर्वरक वितरण, मूल्य समर्थन योजना और जन औषधि केन्द्र जैसे कार्यों में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। साथ ही, मेरठ और गौतम बुद्ध नगर के दो सचिवों जयप्रकाश मिश्रा और शिवदत्त शर्मा को उनके द्वारा सहकारी निधि की रक्षा करते समय किए गए साहसिक कार्यों के लिए वीरता सम्मान प्रदान किया गया। दोनों अधिकारियों ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए लाखों रूपये की निधि को अपराधियों से बचाया और बैंक में जमा कराया।

इस अवसर पर उपस्थित मंत्री डा. अरूण कुमार सक्सेना ने पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता पर बल देते हुए 9 जुलाई को "एक पेड़ माँ के नाम" अभियान में सहकारिता विभाग की सहभागिता सुनिश्चित करने का आह्वान किया।

उन्होंने पूर्व वर्षों में सहकारिता विभाग द्वारा किए गए वृक्षारोपण प्रयासों की सराहना की और इस वर्ष भी उसे पूर्ण लक्ष्य के साथ संपन्न करने की अपेक्षा जताई। मंत्री श्री राठौर ने सहमति जताते हुए वृक्षारोपण को वृहद स्तर पर संपन्न कराने हेतु 91 सहकारी वाटिकाओं की स्थापना का लक्ष्य उपस्थित अधिकारियों को सौंपा।

मंत्री श्री राठौर ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सहकारिता अब आंदोलन नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम बन चुकी है। उन्होंने जानकारी दी कि 1 से 30 सितम्बर 2023 तक आयोजित सदस्यता महाभियान में प्रदेश भर से लगभग 30 लाख नए सदस्य जुड़े और 70 करोड़ रूपये का अंशधन एकत्र हुआ। यह दर्शाता है कि सहकारिता अब प्रदेश के नागरिकों के विश्वास का केंद्र बन चुकी है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में सहकारी समितियों को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। कृषकों को उर्वरकों की निर्बाध आपूर्ति हेतु 6700 एम-पैक्स समितियों को 10-10 लाख रूपये की ब्याजमुक्त कैश क्रेडिट लिमिट स्वीकृत की गई है, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 15 लाख रूपये करने की घोषणा की जा चुकी है। सहकारी समितियों के जीर्ण-शीर्ण भवनों के सुदृढ़ीकरण हेतु 980 एम-पैक्स का कार्य 70 करोड़ रूपये की लागत से पूर्ण हो चुका है तथा वर्ष 2025-26 में 30 करोड़ रूपए और सहायता प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की सौर ऊर्जा योजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में 258 एम-पैक्स समितियों पर 5 करोड़ रूपये की लागत से सोलर पैनल लगाए गए हैं। उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक को यूआईडीएआई द्वारा नामांकन एजेंसी के रूप में शामिल किया गया है, जिससे वह देश का पहला राज्य सहकारी बैंक बन गया है जो आधार से संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराएगा। भविष्य में जिला सहकारी बैंक एवं एम-पैक्स द्वारा भी यह सेवाएं दी जाएंगी।

बलरामपुर जनपद में नया जिला सहकारी बैंक स्थापित किए जाने की प्रक्रिया राज्य सरकार की बजटीय सहायता से प्रगति पर है। सहकार से समृद्धि योजना के तहत एम-पैक्स समितियों का कंप्यूटरीकृत डेटाबेस पीसीयू पर आधारित बनाकर कार्यों की मानिटरिंग सरल की गई है। साथ ही मंत्री श्री राठौर ने आईसीसीएमआरटी के प्रशिक्षकों का मानदेय 10,000 से बढ़ाकर 15,000 रूपये करने की तैयारी है।

कार्यक्रम में प्रमुख सचिव सहकारिता सौरभ बाबू ने स्वागत भाषण देते हुए सहकारिता मंत्रालय एवं प्रदेश सरकार द्वारा किए गए नवाचारों और योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम के अंत में आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता योगेश कुमार ने सभी उपस्थित जनों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कार्यक्रम की सफलता हेतु सभी अधिकारियों, आयोजकों और प्रतिभागियों को बधाई दी।

इस अवसर पर मिशन निदेशक एसआरएलएम श्रीमती दीपा रंजन, पूर्व कुलपति केजीएमयू, वरिष्ठ अधिकारीगण, शीर्ष सहकारी संस्थाओं एवं जिला सहकारी बैंकों के अध्यक्षगण, प्रबंध निदेशक तथा सहकारिता विभाग के अधिकारीगण उपस्थित रहे। ❑❑

उ0प्र0 आउटसोर्स सेवा निगम प्रदेश की प्रशासनिक प्रणाली में एक नई पारदर्शिता और जवाबदेही का अध्याय जोड़ेगा

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लाखों आउटसोर्सिंग कार्मिकों के श्रम अधिकारों, पारिश्रमिक और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा के लिए उ0प्र0 आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को मंजूरी दी

❑ सभी आउटसोर्सिंग कार्मिकों का पारिश्रमिक प्रत्येक माह की 05 तारीख तक सीधे उनके बैंक खाते में भेजा जाए तथा ई0पी0एफ0 और ई0एस0आई0 की रकम समय से जमा हो।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के लाखों आउटसोर्सिंग कार्मिकों के श्रम अधिकारों, पारिश्रमिक और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (UPCOS) के गठन को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि यह निगम प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के साथ-साथ आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के जीवन में स्थायित्व और भरोसा सुनिश्चित करेगा।

मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में प्रस्तावित उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम की कार्यप्रणाली, संरचना और दायरे के सम्बन्ध में विस्तृत विचार-विमर्श किया। इस अवसर पर उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार श्रमिकों के श्रम, सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए कृतसंकल्पित है। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के सामाजिक व आर्थिक हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान व्यवस्था में आउटसोर्सिंग एजेंसियों का चयन विकेन्द्रीकृत तरीके से होता है। जिसके कारण समय पर वेतन न मिलना, वेतन में कटौती, ई0पी0एफ0/ई0एस0आई0 लाभों से वंचित रहना, पारदर्शिता की कमी और उत्पीड़न जैसी अनेक शिकायतें मिलती हैं। इस परिप्रेक्ष्य में सम्पूर्ण व्यवस्था में व्यापक सुधार आवश्यक है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रस्तावित निगम का गठन कम्पनी एक्ट के तहत किया जाए। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक 'बोर्ड आफ डायरेक्टर्स' और एक महानिदेशक की नियुक्ति की जाएगी। मण्डल व जिला स्तर पर भी समितियों का गठन किया जाएगा। एजेंसियों का चयन जेम पोर्टल के माध्यम से न्यूनतम तीन वर्षों के लिए किया जाएगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि वर्तमान कार्यरत कार्मिकों की सेवाएं बाधित न हों और चयन प्रक्रिया में उन्हें अनुभव के आधार पर वेटेज मिले।

मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया कि सभी आउटसोर्सिंग कार्मिकों का पारिश्रमिक प्रत्येक माह की 05 तारीख तक सीधे उनके बैंक खाते में भेजा जाए तथा ई0पी0एफ0 और ई0एस0आई0 की रकम समय से जमा हो। साथ ही, ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0सी0 तथा बैंकों से अनुमन्य सभी लाभ भी कर्मचारियों को प्रदान किए जाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि निगम को रेगुलेटरी बाडी की भूमिका में रखा जाए, जो एजेंसियों की कार्यप्रणाली की निगरानी करे और नियमों के उल्लंघन पर ब्लैकलिस्टिंग, डिबारमेण्ट, पेनाल्टी एवं वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करे। प्रस्तावित निगम द्वारा की जाने वाली सभी नियुक्तियों में एस0सी0, एस0टी0, ओ0बी0सी0, ई0डब्ल्यू0एस0, महिला, दिव्यांगजन और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण प्रावधानों का पूर्णतः पालन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने निराश्रित, तलाकशुदा व परित्यक्त महिलाओं को भी प्राथमिकता देने की बात कही है।

मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि नियमित पदों के विरूद्ध कोई भी आउटसोर्सिंग सेवा नहीं ली जाए। चयन के बाद कोई भी कार्मिक तब तक सेवा से मुक्त न किया जाए, जब तक सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी की संस्तुति न हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक कर्मचारी की गरिमा, सुरक्षा और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम प्रदेश की प्रशासनिक प्रणाली में एक नई पारदर्शिता और जवाबदेही का अध्याय जोड़ेगा। इससे न केवल राज्य के लाखों आउटसोर्सिंग कर्मियों को लाभ मिलेगा, बल्कि प्रशासनिक दक्षता भी बढ़ेगी।

उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन का गठन किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को प्रदान की गयी स्वीकृति

मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन का गठन किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। मंत्रिपरिषद द्वारा उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के गठन हेतु यथावश्यकता नियम/विनियम बनाए जाने/संशोधन किए जाने आदि के लिए निर्णय लेने हेतु मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।

श्रम एवं सेवायोजन विभाग द्वारा प्रदेश के रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों (जाब सीकर्स) को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का कार्य किया जाता है। वर्तमान में अन्तर्राष्ट्रीय रोजगार पिछले कुछ वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण कारक के रूप में उभरा है। इसके अतिरिक्त, देश-विदेश में रोजगार की मांग का सर्वेक्षण करना, प्रतिष्ठित कम्पनियों को सूचीबद्ध करना तथा उनसे रोजगार की मांग एकत्रित करने की प्रणाली विकसित करना, बेरोजगार अभ्यर्थियों के स्किल गैप का अध्ययन करना तथा इस गैप को पूरा करना जैसी महत्वपूर्ण गतिविधियों को किया जाना आवश्यक है।

अभ्यर्थियों को विदेशों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए भाषा प्रशिक्षण एवं प्रस्थान-पूर्व उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित करना, कैम्पस प्लेसमेण्ट एवं कैरियर काउंसलिंग, नियोजित अभ्यर्थियों को प्लेसमेण्ट के बाद सहायता प्रदान करना आदि महत्वपूर्ण गतिविधियों को भी किया जाना आवश्यक है।

अतः वर्तमान परिदृश्य के अनुसार उपर्युक्त कार्यों हेतु 'उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन' का गठन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के संचालन हेतु पांच समितियों यथा-शासी परिषद, राज्य संचालन समिति, राज्य कार्यकारिणी समिति, राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई (एस0पी0एम0यू0) एवं जिला कार्यकारिणी समिति का गठन किया जाएगा। उपरोक्त संगठनात्मक संरचना के आधार पर मिशन को सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम-1860 के अन्तर्गत पंजीकृत किया जाएगा।

यह एक उच्चस्तरीय संस्था होगी, जिसका उद्देश्य यह होगा कि प्रदेश के बेरोजगार अभ्यर्थियों एवं श्रमिकों को उनकी योग्यता के अनुसार प्रदेश एवं विदेशों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जा सके।

विदुर प्रेरणा ब्रांड ग्रामीण महिला उद्यमिता का बना प्रेरणादायक मॉडल

लखनऊ। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के कुशल मार्गदर्शन में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को स्वावलंबी व आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है और इस दिशा में सरकार द्वारा अनेकानेक महत्वाकांक्षी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है।

जनपद बिजनौर में संचालित विदुर प्रेरणा ब्रांड पहल, आज उत्तर प्रदेश में ग्रामीण महिला उद्यमिता का एक प्रेरणादायक मऱडल बन चुकी है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाते हुए, स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग, बाजार उपलब्धता और ग्रामीण स्टार्टअप संस्कृति को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

विदुर प्रेरणा ब्रांड ने अब तक 5, करोड़ 87 लाख का टर्नओवर दर्ज किया है। यह उपलब्धि यह दर्शाती है कि अगर ग्रामीण महिलाओं को सही संसाधन, प्रशिक्षण और बाजार समर्थन मिले, तो वे भी एक स्थायी उद्यम माडल खड़ा कर सकती हैं। विदुर ब्रांड के तहत स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं 150 से अधिक गुणवत्तायुक्त उत्पादों का निर्माण कर रही हैं।

खाद्य उत्पाद में शुद्ध शहद, 18 वैरायटी के मसाले, अचार (नींबू, आम, मिक्स), आंवला कैंडी, टोस्ट, बिस्किट, नमकीन, रागी चिप्स, टमाटर कैचप, मल्टीग्रेन आटा, बाजरा आटा, सरसों और तिल का तेल, सैनिटरी पैड, साबुन डिटर्जेंट, टायलेट क्लीनर, बाथरूम क्लीनर, धूप बत्ती,लोर क्लीनर, हस्तशिल्प व खिलौने टेडी बियर, लकड़ी के टी कोस्टर, क्च्च् के अंतर्गत सजावटी लकड़ी, हस्तशिल्प आदि का निर्माण समूहों की दीदियां कर रही हैं।

इलेक्ट्रानिक्स व तकनीकी उत्पाद के अन्तर्गत LED बल्ब (5W, 9W, 12 W), Vidur-EV - महिला समूहों द्वारा असेंबल की गई इलेक्ट्रिक स्कूटी,एग्रो-बेस्ड उत्पाद, जैविक खाद (वर्मी कम्पोस्ट) पौधशाला उत्पाद-पपीता, अमरूद, टमाटर,पोषण वाटिका किट, सीज़नल नर्सरी पैक, विपणन नेटवर्क आदि कार्य किये जा रहे हैं।

बिजनौर में 150+ से अधिक पंचायत स्तरीय विदुर स्टोर, 44 CLF (क्लस्टर लेवल फेडरेशन) स्तर के विदुर ब्रांड आउटलेट, 560 PDS दुकानों पर विदुर किट और 28 Vidur Vans द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विक्रय किया जा रहा है। 18 नगर पालिका और नगर पंचायत स्तर पर विदुर ब्रांड आउटलेट, पेट्रोल पंपों पर विदुर कैनोपी बिक्री रूटाल संचालित हैं। 10,738 महिला सदस्य सीधे तौर पर विदुर ब्रांड के उत्पादन, पैकेजिंग और बिक्री से जुड़ी हुई हैं। ये महिलाएं आत्मनिर्भर बनकर अपने परिवार और समुदाय में प्रेरणा का स्रोत बन रही हैं।

राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की मिशन निदेशक श्रीमती दीपा रंजन ने बताया कि विदुर प्रेरणा ब्रांड न केवल एक उत्पाद ब्रांड है, बल्कि यह ग्रामीण भारत की आत्मनिर्भरता, महिला सशक्तिकरण और स्थानीय नवाचारों का प्रतीक बन गया है।

जलशक्ति मंत्री ने गोमती जलसेतु (एक्वाडक्ट) शारदा सहायक पोषक नहर के दाहिने तट पर किया वृक्षारोपण

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने वृहद वृक्षारोपण अभियान-2025 के तहत ग्राम नूरपुर बेहटा, तहसील मोहनलालगंज, लखनऊ में शारदा सहायक पोषक नहर के दाहिने तट पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों में साथ पौधारोपण किया। इस अवसर पर लगभग 800 पौधों का रोपण किया गया। जिनमें मुख्य प्रजातियां सागौन, बरगद, पीपल, आम, बेल, नीम, पाकड़, जामुन, मोहगनी आदि का रोपण किया गया। उल्लेखनीय है कि वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा भी प्रदेश स्तर पर पौधों का रोपण किया जाएगा।

इस अवसर पर प्रमुख सचिव सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग अनिल गर्ग, प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष संदीप कुमार, प्रमुख अभियंता हर प्रसाद, प्रमुख अभियंता अशोक कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।